ISSN No. 2231-0045 VOL.II* ISSUE-IV*MAY-2014
Periodic Research

भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा की दशा एवं दिशा (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

सेराफिनुस किस्पोट्टा
सहायक प्राध्यापक
विभाग अर्थशास्तत्र
गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
बिलासपुर, छ. ग.

गजानन कटरे
शोधार्थी
विभाग अर्थशास्त्र
गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
बिलासपुर, छ. ग.

सारांश

भारत में आजादी के बाद से ही सब के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। देश विभाजन के बाद भारत का अधिकांश अन्न उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जिससे भारत में अनाज उत्पादन का औसत स्तर घट गया। खाद्य सुरक्षा सें आशय ''आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संतुलित आहार प्राप्त कर सकनें, पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरण की सफाई, एवं प्रारम्भिक स्वास्थ्यचर्या से है।'' इस शोध पत्र का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति का अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द : अर्थव्यवस्था, संकट, खाद्यान्न,सुरक्षा, कैलोरी, कानून, अनाज

प्रस्तावना

वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है। यह मुद्दा पूर्णतया कृषि एवं फसल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यहॉ के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था और जीवन शैली पूर्णतया कृषि सें प्रत्यक्ष नियंत्रित होती है। देश की कुल आबादी 70 प्रतिशत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।[1] वर्तमान में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि मात्र 0.10 हेक्टेयर है, जबकि यह 1951 में 0.30 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति थी। जबकि विश्व में औसत प्रति व्यक्ति भूमि 4.2 हेक्टेयर उपलब्ध है।[2] भारत में भूमि जोंत बढ़ती जनसंख्या के कारण तेजी से घट रही है। भारतीय कृषि जोंत का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग छोटे एवं सीमांत कृषक के पास है, जिसमें इन्हें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य उपलब्ध नहीं हो पाता।

भारत में आजादी के बाद से ही सब के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। देश विभाजन के बाद भारत का अधिकांश अन्न उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जिससे भारत में अनाज उत्पादन का औसत स्तर घट गया। खाद्य सुरक्षा सें आशय ''आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संतुलित आहार प्राप्त कर सकनें, पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरण की सफाई, एवं प्रारम्भिक स्वास्थ्यचर्या से है।'' भारत में खाद्य वितरण का कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जिसमें व्यापक काला बाजारी एवं भ्रष्टाचार है।[3] (ऋतिका खेरा–2010) भारत की खाद्य सुरक्षा नीति की दक्षता पर प्रभाव जैसे।(1) अपर्याप्त भण्डारण के कारण प्रभावित हो रहा है, (2) पी0डी0एस0 प्रणाली में त्रुटि होने के कारण इसके लाभ से बहुत से वास्तविक गरीब वंचित हैं (और गैर गरीब शामिल किए गये हैं) और अधिक गम्भीर है। (3) सब्सिडी प्राप्त अधिशेष खाद्यान्न अन्य देशों को निर्यात किया जाता है।

खाद्य असुरक्षा की स्थिति, 2000, नामक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस विश्व में लगभग जनसंख्या का आधा भाग भूख के प्रति संवेदनशील है। उनमें 1/7 अल्प पोषित हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को देश की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश मे किसानों के लिए लाभकारी मूल्य एवं उचित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना विभाग का उद्देश्य है। खाद्य सुरक्षा की चुनौती उसकी सम्भावना का स्तर प्राप्त करके विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य की व्यवस्था नीतिगत पहल है। इस पहल के तहत ही अगस्त 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल,गेहूँ और मोटे अनाज क्रमशः तीन दो और एक रूपये की एक समान कीमत पर सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का अध्ययन.
2. खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एवं खपत का अध्ययन ।

शोध विधि

प्रस्तुत विश्लेषणात्मक शोध हेतु द्वितीयक समंक का उपयोग किया गया है, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि सांख्यिकी **एन. एस. एस. ओ. दौर तथा सी. ए. सीपी** की रिर्पोट आदि से संकलित किया गया है। आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण हेतु डायग्राम का उपयोग किया गया है।

समंक विश्लेषण

भारत में खाद्यान्न के क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता विभिन्न वर्ष इस प्रकार है

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1950-51	97.3	50.8	522
1960-61	115.6 (19%)	82.0	710
1970-71	124.3 (8%)	108.4	872
1980-81	126.7 (2%)	129.6	1023
1990-91	127.8 (1%)	176.36	1380
2000-01	121.0 (-5%)	196.81	1626
2009-10	121.3 (.3%)	218.2	1798
2010-11	126.7 (5%)	244.5	1930
2011-12	125.0 (-1%)	257.4	2059

(क्षेत्रफल मिलियन हेक्टयर में है, उत्पादन मिलियन टन में है और उत्पादकता प्रति हेक्टर किलोग्राम में है।)

स्त्रोतः– आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13, (कृषि सांख्यिकी 2012ए पृष्ठ – 60) (क्षेत्रफल मिलियन हेक्टयर में हैं)

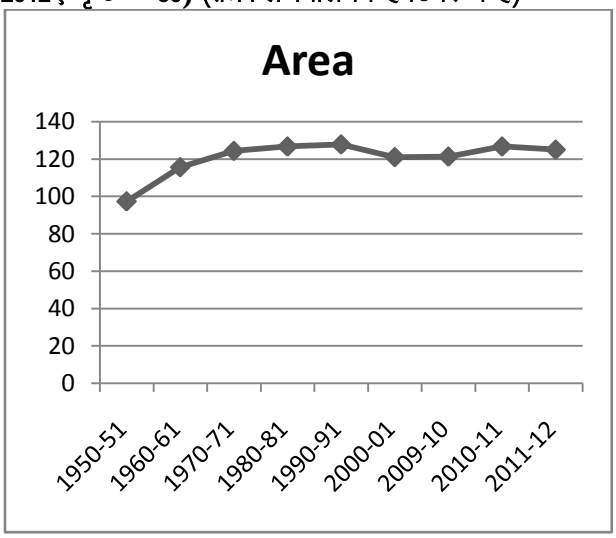

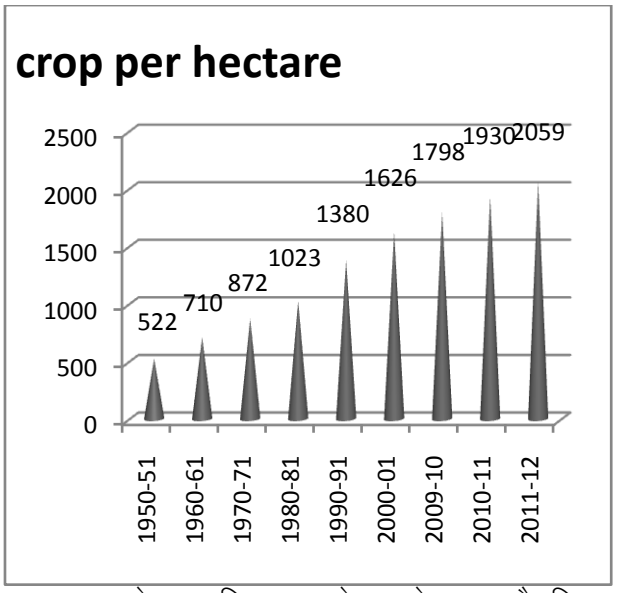

उपरोक्त तालिका अवलोकन से स्पष्ट है कि 1950–51 से 60 वर्ष की अवधि में खाद्यान्नों के अधीन क्षेत्रफल में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह वृद्धि भिन्न भिन्न दशक में भिन्न भिन्न स्तर से हुई है 1951–61 के वर्ष में 19 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वर्ष 1961–71 में 8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि 1971–81 और 1981–91 के बीच बहुत कम लगभग 2 प्रतिशत व 1 प्रतिशत तक क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। 1991–2001 के बीच 5 प्रतिशत तक की कमी हुई है। 2001 से 2010 के बीच क्षेत्रफल में कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ है। वर्ष 2010–11 में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 2011–12 में क्षेत्रफल में 1 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 1991 में अपनाये गये आधुनिक आर्थिक सुधार के बाद क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत की कमी हुई है जो कृषि फसल स्थानांतरण व आधुनिकीकरण का प्रभाव प्रदर्शित करता है।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि 1951–61 के दौरान 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 1961–71 के बीच 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसी बीच हरित क्रान्ति को अपनाया था जिसका उत्पादन पर खास प्रभाव दृष्टिगत नही होता 1971–81 के बीच 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, 1981–91 के दौरान 3.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई खाद्यान्न उत्पादन में न्यूनतम वृद्धि 1991–2010 के सुधार काल के बीच 1.1 प्रतिशत की न्यून वृद्धि प्राप्त हुई है जिससे खाघान्न उत्पादन में कमी आई है। 1951 से लेकर 2010 की संयुक्त अवधि में खाघान्न वृद्धि दर लगभग 2.5 प्रतिशत प्राप्त हुई है जबकि इस बीच जनसंख्या वृद्धि की दर 2.04 प्रतिशत रही है। (भारत 2013) अतः स्पष्ट है कि खाद्यान्न उत्पादन में वांछनीय वृद्धि न होना खाद्य सुरक्षा के लिये संकट उत्पन्न कर रहा है।

प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1950–51 में 522 किलोग्राम था 1951–61 के दशक में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 710 किलोग्राम के स्तर पर पहूचा 1961–71 के बीच हरित क्रांति के काल में प्रति हेक्टेयर उपज में 2. 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होकर 872 किलोग्राम हुई।

1971–81 के बीच 1.6 प्रतिशत के बीच 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1981 से 91 के बीच 3 प्रतिशत की वृध्दि के साथ प्रति हेक्टेयर उपज 1380 किलोग्राम हुआ 1991–2000 के बीच 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और यह 1626 के स्तर पर पहूॅचा वर्ष 2011–12 में खाद्यान्न उत्पादन उपज का प्रति हेक्टेयर 2059 के स्तर पर पहुंचा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस वर्ष कृषि उपज में वृद्धि का यह अधिकतम वर्ष है। परन्तु अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। अत– निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1951–2010 की अवधि में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई परन्तु उत्पादकता में कोई विशेष उपलब्धि अर्जित नही हो सकी।

भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत

वर्ष	शहरी 30 दिन खपत कि.ग्रा. में	शहरी दैनिक खपत ग्राम में	ग्रामीण 30 दिन खपत कि. ग्रा. में	ग्रामीण दैनिक खपत ग्राम में
1972-73	15.26	509	11.24	375
1977-78	15.25	508	11.62	387
1982-83	14.47	493	11.30	377
1987-88	14.47	482	11.19	373
1993-94	13.30	447	10.63	354
2004-05	12.12	404	9.94	331
2009-10	11.35	378	9.39	313

स्त्रोतः– आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय कृषि और सहकारिता विभाग (एन.एस.एस.ओ. 68 दौर)

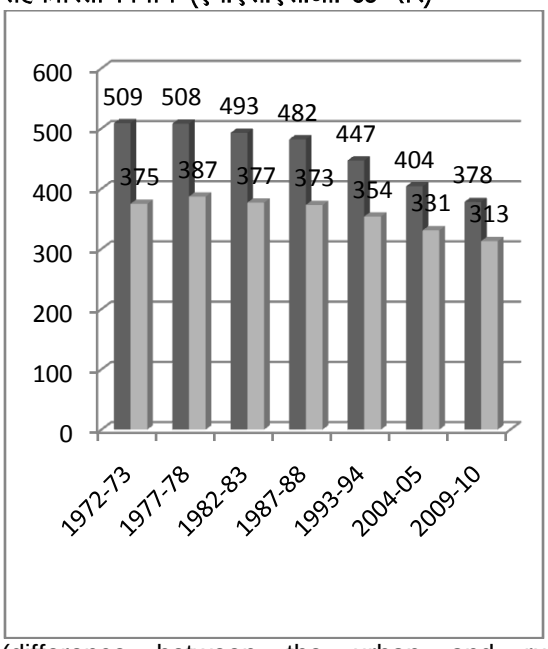

(difference between the urban and rural consumption in grams in per day)

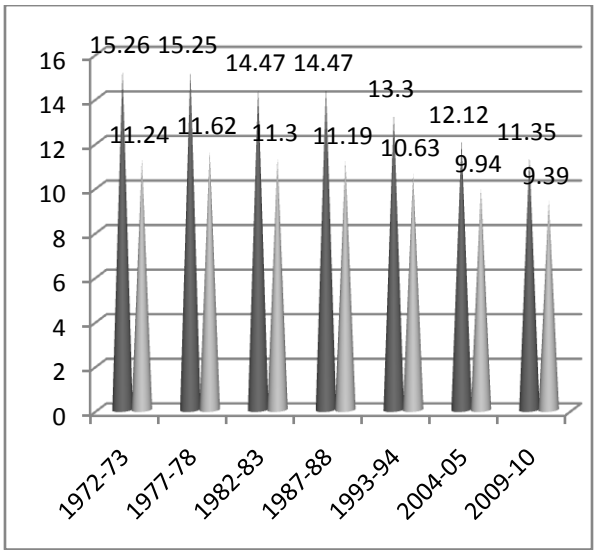

(difference between the urban and rural consumption kilograms in 30 days)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की खपत का अनुमान हर पॉच वर्ष के अन्तराल पर एन.एस.एस.ओ. द्वारा संचालित परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर 1972–73 में शहरी क्षेत्र में 15.26 कि.ग्रा. तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11.24 कि.ग्रा. मासिक खाद्यान्न खपत और शहरी क्षेत्र में 509 ग्राम व ग्रामीण क्षेत्र में 375 ग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग किया गया है। इसी प्रकार 1977–78 में शहरी क्षेत्र में 15.25 कि.ग्रा. तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11.62 कि.ग्रा. मासिक खाद्यान्न खपत और शहरी क्षेत्र में 508 ग्राम व ग्रामीण क्षेत्र में 387 ग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग किया गया है। वर्ष 1982–83 में 14.8 कि.ग्रा. शहरी क्षेत्र में 11.30 कि.ग्रा. ग्रामीण क्षेत्र में मासिक उपभोग तथा 493 ग्राम शहरी क्षेत्र में और 377 ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग प्राप्त हुआ है। 1987–88 में 14.47 कि.ग्रा. शहरी क्षेत्र में 11.19 कि.ग्रा. ग्रामीण क्षेत्र में मासिक उपभोग तथा 482 ग्राम शहरी क्षेत्र में और 373 ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग प्राप्त हुआ है। 1993–94 में 13.40 कि.ग्रा. शहरी क्षेत्र में 10.63 कि.ग्रा. ग्रामीण क्षेत्र में मासिक उपभोग तथा 447 ग्राम शहरी क्षेत्र में और 354 ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग प्राप्त हुआ है। वर्ष 2004–05 में 12.12 कि.ग्रा. शहरी क्षेत्र में 09. 94 कि.ग्रा. ग्रामीण क्षेत्र में मासिक उपभोग तथा 404 ग्राम शहरी क्षेत्र में और 331 ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग प्राप्त हुआ है। 2009–10 में 11.35 कि.ग्रा. शहरी क्षेत्र में 09.39 कि.ग्रा. ग्रामीण क्षेत्र में मासिक उपभोग तथा 378 ग्राम शहरी क्षेत्र में और 313 ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग प्राप्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि 1973–78 के बाद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मासिक एवं दैनिक स्तर पर खाद्यान्न की खपत में निरन्तर कमी हुई है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धताः–

वर्ष	चावल	गेंहू	अन्य अनाज	कुल अनाज	दलहन	खाघान्न
1951	158.9	65.7	109.6	334.2	60.7	394.9
1961	201.1	79.1	119.5	399.7	69.0	468.7
1971	192.6	103.6	121.4	417.6	51.2	468.7
1981	197.8	129.6	89.9	417.3	37.5	454.8
1991	221.7	166.8	80.0	468.5	41.6	510.1
2001	190.5	135.8	56.2	386.2	30.0	416.2
2005	177.3	154.3	59.4	390.9	31.5	422.9
2009	188.4	154.7	63.9	407.0	37.0	444.0
2010	185.4	159.0	60.0	404.4	35.4	439.8

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि एवं सहकारिता विभाग पृष्ठ 102

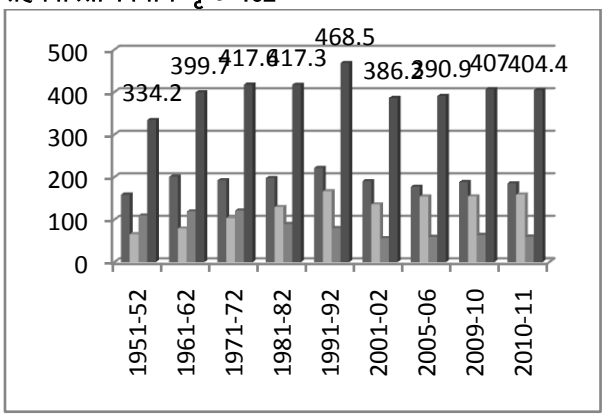

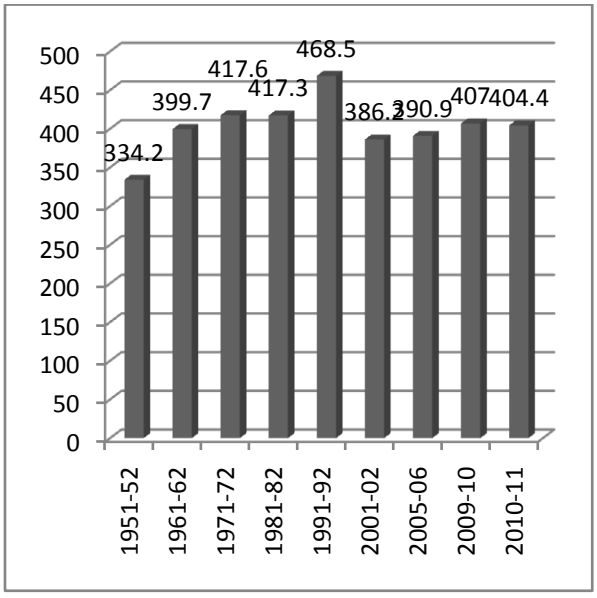

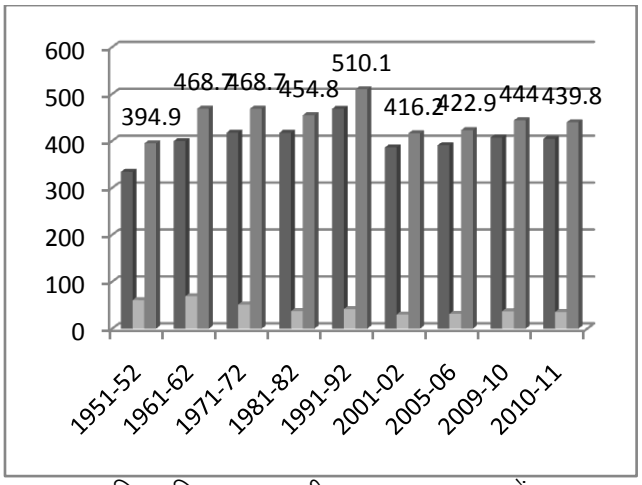

प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 1951 में 395 ग्राम थी जिसमें चावल 159 ग्राम, गेहू 65.7 ग्राम, अन्य अनाज 109.6 ग्राम इस प्रकार कुल अनाज 334 ग्राम तथा दलहन की मात्रा 60.7 ग्राम थी। खाद्यान्न उपलब्धता में परिवर्तन होकर वर्ष 2010 में 444 ग्राम हो गया जिसमें चावल 185 ग्राम गेहू 159 ग्राम तथा अन्य अनाज 60 ग्राम इस प्रकार कुल अनाज 404 ग्राम तथा दलहन 35.4 ग्राम के स्तर पर पहुँच गया अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है की चांवल एवं गेहू की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। परन्तु अन्य अनाज एवं दलहन की उपलब्धता में क्रमशः –42 एवं –40 प्रतिशत की कमी आई है। जबकि कुल अनाजों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

बीमार राज्यों में कैलोरी उपभोगः–

राज्य	1972.73		1993.94		1999.2000		2009.10	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
C.G							1949	1926
U.P	2161	2527	2114	2307	2131	2327	1923	2064
Bihar	2167	2225	2188	2115	2171	2121	2013	1931
M.P	2229	2423	2082	2164	2132	2062	1854	1939
Raj	2357	2730	2184	2470	2335	2429	2014	2191
India	2107	2266	2071	2153	2156	2149	1946	2020

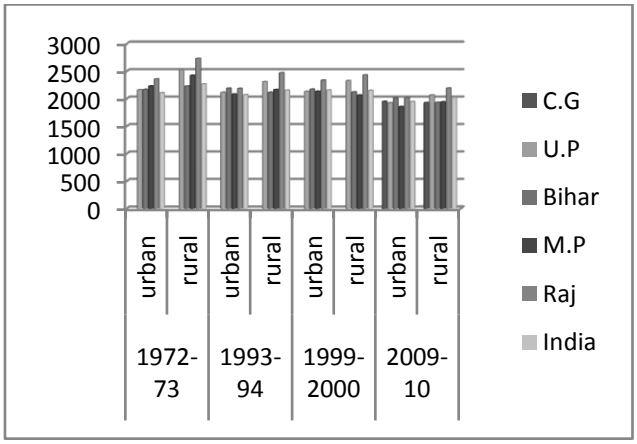

छत्तीसगढ में 2009–10 में शहरी क्षेत्र में 1949 कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1926 कैलोरी है जबकि भारत वर्ष में 1940 शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2020 कैलारी उपभोग है, 1972–73 से कैलोरी उपभोग में निरन्तर कमी हो रही है जो वेहद चिन्तनीय है कैलोरी उपभोग के राष्ट्रीय मानक योजना आयोग के द्वारा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी रखा गया है गरीबी के इस स्तर को योजना आयोग पूर्ण गरीबी मानता है। अतः भारत में कैलोरी उपभोग का पैमाना निर्धारित राष्ट्रीय मानक से कम है। जो खाद्य की कमी की ओर इंगित करता है।

निष्कर्ष

वर्ष 1951 से वर्ष 2010 के बीच खाद्यान्न क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि तो हुई है परन्तु आधुनिकीकरण एवं नये आर्थिक सुधार का क्षेत्रफल वृद्धि में विशेष प्रभाव नही हुआ। 1950–51 से 2010–11 तक चार गुना से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरुप उत्पादन नही बढा। प्रति हेक्टर उपज 1951 में 522 कि.ग्रा. के स्तर पर थी जो बढकर 2010–11 में 1930 कि.ग्रा. के स्तर पर पहूचा जो आवश्यक खाद्य की मात्रा के अनुरुप नही है। प्रतिदिन एवं प्रतिमाह कैलोरी के मामले में अनाज की खपत 1972–73 से निरन्तर कम हुई है। यह घटकर 2009–10 में 11.35 कि.ग्रा. प्रतिमाह तथा 378 ग्राम शहरी क्षेत्र में एवं 9.39 कि.ग्रा. तथा 313 ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में अनाज की उपलब्धता रही है। कैलोरी उपभोग के मामले में एन.एस.एस.ओ. के भिन्न भिन्न दौर में कैलोरी उपभोग में कमी आई है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हमारा देश खाद्य की कमी से प्रभावित हो रहा है जनसंख्या व आय वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की मांग तीव्र गति से बढ रही है किन्तु खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नही हो रही है इस कारण मांग एवं पूर्ति में असतुंलन पैदा हो रहा है। जो खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा है।

सुझाव

1. सरकार को उचित भूमि सुधार एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम लागू करना चाहिये।
   जैसे– अतिरिक्त कृषि भूमि सृजन कार्यक्रम एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।
2. कृषि उपज एवं उत्पादन के लिये अनुसंधान एवं बीज प्रगुणन कार्यक्रम का तीव्र समावेश करना चाहिये।
3. प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये जिससे कृषि क्षेत्र पर कम भार आये।
4. खाद्यान्न उत्पादन के प्रति लोगों को जागरुकता संबंधी कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये।
5. खाद्यान्न उपभोग के प्रति लोगों को जागरुक बनाना जिससे खाद्यान्न की बचत की जा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, सृजित (2006). फार्मर सुसाईड इन महाराष्ट्रा, इन्दिरा गॉधी विकास अनुसंधान संस्थान नवी मुम्बई।
2- गुलाटी अशोक (2007): Agriculture Diversification towards high value commodity: A study in food surplus status in India with focus on Andhra Pradesh and Punjab, International Food Policy Research Institute, Washigton, D.G. (March 2007).
3- Sheeran, Josette, (2008), The Guardian, "There is food on shelves but people are priced out of the market". The Guardian,26 February, 2008.
4- K.V. Aiahanna and S.E. Mahadevappa (2009), "PDS as food security to Agricultural Laabourers – A study", Southern Economist, January1,2009, Pp 13-14.
5. खेरा, रीतिका (2010), इन्डियॉज पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम : युटिलाईजेशन एण्ड इम्पैक्ट, जर्नल ऑफ डेवेलपमेंट स्टडीज।
6. पराते,संजय (सितम्बर 2010)''खाद्यान्न सुरक्षा,पीडीएस और छत्तीसगढ, जनमत स्वर, शिवाजी नगर भोपाल, पृष्ठ संख्या, 12–13।
7. ढिल्लन,बी0एस0 एवं अन्य (2010),नेशनल फूड सिक्योरटी विज–ए–विज. सस्टनबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन हाई क्राप प्रोडक्टविटी रिजन्स,करेन्ट साइन्स वाल्यूम–98,नं0 –01,जनवरी – 2010।
8. वैद्यनाथन, ए. (2010), एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली,
9. सुन्दरम्, जोमों क्वामे (2010),लेशन्स फ्राम द 2008 वर्ल्ड फूड क्राइस, ईकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकली वीकली मार्च 20, 2010 पृष्ठ संख्या 35–40।
10. चन्द, रमेश (2010),अन्डरस्टैन्डिंग द नेचर एन्ड द काजेज ऑफ फूड इनफ्लेशन ईकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकली वीकली फरवरी 27, 2010 पृष्ठ संख्या 10–13।
11. पटनाइक, उत्सा (2011) हॉऊ लिटिल कैन ए पर्सन लिव आन,द हिन्दु, 30 सितम्बर 2011।
12. सिंह,निरंकार (2011) बिना खाद्यान्न सुरक्षा कैसे, हरिभुमि बिलासपुर संस्करण, 29 दिसम्बर 2011, पृष्ठ संख्या 6।
13. भारतीय कृषि की स्थिति, (2011–12), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
14. हर्ष,मंदर (2012).असमानता की खांई को पाटने का अवसर, दैनिक भास्कर, 6 जनवरी 2012, पृष्ठ संख्या 4।
15. आर्थिक सर्वेक्षण (2012–13),सूचना एवं प्रसारण विभाग, नई दिल्ली।
16- Hanchinal, R.R. (2012), Viability of small and Marginal farmers in India: An Overview of Initiatives by the Government of Karnataka, Agricutural Situation in india, Dec. 2012, New Delhi, page – 499-503.
17. Sinha, Deepa, (2013), Cost of implementing the National Food Security Act, Economic and Political Weekly, Sept.28, 2013, Page 31-34.